

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 23 जनवरी, 2015

विषय: राजीव आवास योजनान्तर्गत नगरपालिका परिषद, नैनीताल हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 89/RAY/2014-15, दिनांक 04.06.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: G-20011/3/2014/BSUP(RAY)/JNNURM(FTS-10486), दिनांक 19.05.2014 द्वारा राजीव आवास योजनान्तर्गत राज्य की 05 नगर निकायों हेतु प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि ₹1168.98 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा नगरपालिका परिषद, नैनीताल हेतु स्वीकृत परियोजना लागत ₹547.14 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए परियोजना हेतु प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश ₹153.58 लाख तथा उसके सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश ₹42.36 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि ₹195.94 लाख (रुपये एक करोड़ पचानवे लाख चौरानवे हजार मात्र) की निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	निकाय का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	निर्मित होने वाले भवनों की संख्या	भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त में अवमुक्त धनराशि	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष देय राज्यांश	कुल अवमुक्त धनराशि (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	नगरपालिका परिषद, नैनीताल	547.14	96	153.58	42.36	195.94

- उक्त धनराशि ₹195.94 लाख (रुपये एक करोड़ पचानवे लाख चौरानवे हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से 03 किस्तों (प्रति किस्त 1/3) में उपलब्ध करायी जायेगी।
- शहरी विकास निदेशालय (एस0एल0एन0ए0), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपरोक्त कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता से पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

- (iii) भारत सरकार द्वारा नामित TIPMA (Third Party Independent Monitoring Agency) की निरीक्षण आख्या का निदेशालय द्वारा परीक्षण किया जायेगा। उक्त आख्या में रेखांकित कमियों को दूर कराने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा आगामी किस्त अवमुक्त की जायेंगी।
- (iv) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा प्रत्येक माह की 02 तारीख तक निर्माण कार्य का प्रगति विवरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों व I-POMS पर शहरी विकास निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (v) योजनान्तर्गत निर्धारित लाभार्थी अंश का भुगतान लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
- (vi) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- (vii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए एवं निर्माण कार्य पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये।
- (viii) योजना के सम्बन्ध में हुई सीएसएमसी की तृतीय एवं सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ix) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों के लिए किया जायेगा, जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
- (x) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों हेतु ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (xi) निदेशक (एस0एल0एन0ए0), नगर निकाय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा RAY Guideline तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xii) परियोजना को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाय।
- (xiii) योजनान्तर्गत बनाये जाने वाले कुल आवासों में अनुसूचित जाति के न्यूनतम 19 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के 04 प्रतिशत व्यक्तियों को अवश्य ही लाभान्वित किया जायेगा।
- (xiv) चूंकि उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या-13 सामान्य बजट, अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जाति उपयोजना बजट एवं अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट से स्वीकृत की जा रही है। अतएव वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों का विवरण पृथक-पृथक अंकित करते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (xv) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगी।
- (xvi) धनराशि का दिनांक 31-3-2015 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक- 2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत- 800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-08-राजीव आवास योजना-'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ 150.87 लाख, अनुदान सं0-30 के लेखाशीर्षक- 2217-शहरी

विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत- 800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-07-राजीव आवास योजना-'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ 37.23 लाख, तथा अनुदान सं0-31 के लेखाशीर्षक- 2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-07-राजीव आवास योजना-'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ 7.84 लाख डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्रसं0- 399/XXVII(2)/2014, दिनांक 26.09.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5- यह आदेश शासनादेश सं0-80/अ0मु0स0/पी0एस0/2014-15, दिनांक 23.04.2014 में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए जारी किया जा रहा है।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी-S.15.2.13.00.2.2....., S.15.2.3.00.0.2.6. एवं S.15.2.2.3.10.0.2.8.... के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्बाल)
सचिव।

सं0-146 (1)/IV(2)-शा0वि0-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड नैनीताल, विकास भवन, भीमताल।
11. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नैनीताल।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओमकर सिंह)
उप सचिव।